



देश की उपासना

देश के विकास में समर्पित समाज के सभी वर्गों के लिए



वर्ष - 04

अंक - 244

जौनपुर शुकवार, 24 अप्रैल 2026

सान्ध्य दैनिक (संस्करण)

पेज - 4

मूल्य - 2 रुपये

संक्षिप्त खबरें 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों के लिए मतदान जारी

कोलकाता, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के महत्वपूर्ण दो चरणों में से पहले चरण के तहत आज गुरुवार सुबह 7 बजे से 16 जिलों में फैली 152 विधानसभा सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। मतदाताओं में इस बार चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखा जा रहा है। कई विधानसभा क्षेत्रों के कुछ मतदान केंद्रों के बाहर सुबह 7 बजे आदि कारिक रूप से मतदान शुरू होने से पहले ही लंबी कतारें लग गई थीं। इस बार मतदाताओं को दो-स्तरीय सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है। पहला सत्यापन केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा मतदान केंद्र परिसर में प्रवेश से पहले किया जा रहा है, और दूसरा संबंधित बूथ-स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) द्वारा मतदान कक्ष में प्रवेश से पहले। रिपोर्ट लिखे जाने तक मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रही। हालांकि, मतदान शुरू होने के समय कुछ मतदान केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) में खराबी की खबरें भी सामने आईं। पश्चिम बर्दवान जिले के औद्योगिक नगर दुर्गापुर के एक मतदान केंद्र पर ईवीएम की बैटरी निष्क्रिय होने के कारण अनिवार्य मॉक पोलिंग समय पर शुरू नहीं हो सकी। इसी तरह, उत्तर बंगाल के दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी और अल्पसंख्यक बहुल मुर्शिदाबाद जिले के बहारामपुर के कुछ मतदान केंद्रों पर भी मॉक पोलिंग नहीं हो पाई। आज गुरुवार को पहले चरण में जिन 16 जिलों में मतदान हो रहा है।

भारत का रक्षा उत्पादन 20 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक, 100 से अधिक देशों को किरा निर्यात

नई दिल्ली, (एजेंसी)। भारत का रक्षा उत्पादन 20 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक हो चुका है। इसके साथ ही आज भारत से 100 से अधिक देशों को लगभग 4 अरब डॉलर के रक्षा उत्पाद निर्यात किए जा रहे हैं। भारत ने मिस्र में आयोजित एक बैठक में यह जानकारी दी। यहां भारत और मिस्र दोनों देशों ने रक्षा उद्योग में संयुक्त विकास और संयुक्त उत्पादन के अवसरों को आगे बढ़ाने पर सहमति जताई है। दरअसल भारत और मिस्र के बीच 11वीं, संयुक्त रक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई है। यह बैठक रक्षा सहयोग को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। यह बैठक मिस्र के काहिरा शहर में आयोजित की गई। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में दोनों देशों ने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और व्यापक बनाने पर गहन विचार-विमर्श किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रक्षा मंत्रालय में अंतरराष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद ने किया। उनके साथ रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे। वहीं, मिस्र की ओर से रक्षा मंत्रालय और सशस्त्र बलों के उच्च अधिकारियों ने भाग लिया।

विशेष टीम गठित कर हो जमीनी विवादों का निस्तारण : मुख्यमंत्री योगी

गोरखपुर, (संवाददाता)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जमीन से जुड़े विवादों का निस्तारण विशेष टीम गठित करके किया जाए। जमीन का मालिकाना हक उसके वास्तविक स्वामी के पास ही होना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति की जमीन पर यदि दबंगों ने कब्जा किया है तो जमीन को कब्जा मुक्त कराने के साथ दोषियों को कानूनी सबक सिखाया जाए। किसी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले बख्शें न जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देते और हर व्यक्ति के जीवन में खुशहाली लाने को संकल्पित है। सीएम योगी



गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। मंदिर परिसर के महंत दिग्विजयनाथ स्मृति सभागार के बाहर कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक वह खुद पहुंचे और एक-एक करके सबकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान करीब 200 लोगों से मुलाकात कर उन्होंने सबको आश्वस्त किया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। सबके प्रार्थना पत्रों को संबंधित अधिकारियों को संदर्भित करते हुए त्वरित और संतुष्टिपरक निस्तारण का निर्देश देने के साथ सीएम ने लोगों को बरोसा

मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीद का लक्ष्य बढ़ाने की मांग की, केंद्र को भेजा प्रस्ताव

भोपाल, (एजेंसी)। मध्य प्रदेश सरकार ने रबी विपणन सत्र 2026-27 के तहत गेहूं खरीद के लक्ष्य को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। राज्य सरकार का कहना है कि इस बार गेहूं की पैदावार अच्छी होने के कारण खरीद मौजूदा लक्ष्य 7.8 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक होने की संभावना है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म श्कस पर जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार इस खूब पर केंद्र के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने लिखा कि बेहतर उत्पादन और बढ़ती खरीद को देखते हुए लक्ष्य बढ़ाने की मांग की गई है। उन्होंने बताया कि शुरुआत में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण कुछ दिक्कतें आई थीं लेकिन सरकार ने समय रहते पर्याप्त संख्या में बोरेों की व्यवस्था कर ली। इनमें नए जूट बैग, पॉलीप्रोपाइलीन (पीपी) बैग और रिसाइकिल किए गए गननी बैग शामिल हैं। अधिकारियों के अनुसार, फिलहाल किसी भी तरह की कमी नहीं है और खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से चल रही है। राज्य में गेहूं खरीद की शुरुआत 9 अप्रैल से कुछ इलाकों में हुई थी, जिसे 15 अप्रैल से पूरे प्रदेश में लागू किया गया। इसके बाद खरीद केंद्रों पर तेजी आई है। इस साल किसानों को प्रति विंटल 2,625 रुपए का भुगतान किया जा रहा है, जिसमें 2,585 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और 40 रुपए प्रति विंटल का राज्य सरकार का बोनस शामिल है।



पीएम मोदी का ममता सरकार पर तंज 'झालमुड़ी मैंने खाई, असर टीएमसी को हुआ'

कोलकाता, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल में गुरुवार को एक ओर जहां पहले चरण के तहत 152 सीटों पर मतदान जारी है, वहीं दूसरे चरण की 142 सीटों के लिए चुनाव प्रचार भी पूरी तेजी पर है। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृष्णनगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सरकार पर जमकर निशाना साधा। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने चुटकी लेते हुए कहा, झालमुड़ी मैंने खाई है लेकिन झाल (मिर्ची) टीएमसी को लगी है। उन्होंने कहा कि 4 मई को बंगाल में भाजपा-एनडीए की जीत का जश्न मनाया जाएगा, मिठाई बांटी जाएगी और झालमुड़ी भी बांटी जाएगी। उन्होंने कहा कि पश्चिम

बंगाल में पहले चरण का मतदान हो रहा है और तमिलनाडु में भी मतदान जारी है। उन्होंने सभी मतदाताओं को शुभकामनाएं देते



हुए अपील की कि इस बार मतदान और उन्हें आत्महत्या का नाम दे के नए रिकॉर्ड बनें और लोकतंत्र के इस पर्व को पूरे उत्साह के साथ मनाया जाए। उन्होंने दावा किया

कि पिछले 50 वर्षों में यह पहला चुनाव है, जिसमें हिंसा सबसे कम हुई है। उन्होंने कहा कि पहले हर हफ्ते हिंसा की घटनाएं होती थीं

की धरती पर लोकतंत्र की प्रतिष्ठा स्थापित की है और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित किया है। साथ ही, उन्होंने सरकारी कर्मचारियों की भी तारीफ की, जो इस बार जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब तक की जानकारी के अनुसार मतदान पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। कृष्णनगर में भय पर भरोसे की जीत का माहौल दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि भय खत्म हो रहा है और भरोसा आगे बढ़ रहा है। जिन लोगों की आवाज सालों से दबाई गई थी, वे अब खुलकर बोल रहे हैं। गांव-गांव, गली-गली, महिला-पुरुष, युवा और बुजुर्ग सभी बदलाव की बात कर रहे हैं।

छत्तीसगढ़ सरकार ने 24 घंटे में वापस लिया कर्मचारियों के राजनीतिक गतिविधियों पर रोक का आदेश

रायपुर, (एजेंसी)। छत्तीसगढ़ की विष्णु देव साय सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को राजनीतिक गतिविधियों से दूर रखने संबंधी अपना आदेश महज 24 घंटे के भीतर वापस ले लिया। इस फैसले ने राज्य में सियासी हलचल तेज कर दी है। बुधवार देर रात जारी निर्देश में कहा गया था कि कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी राजनीतिक दल में पद नहीं रखेगा और न ही राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेगा।



उल्लंघन करने पर सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई थी। हालांकि, इस आदेश का तुरंत विरोध शुरू हो गया। कांग्रेस पार्टी ने इसके समय और मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे नियम पहले से ही पूरे देश में लागू हैं, फिर नया सर्कुलर जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी। कांग्रेस ने यह भी पूछा कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठनों के कार्यक्रमों में भाग लेना भी इन नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इस सवाल ने विवाद को और बढ़ा दिया और सरकार पर स्पष्टीकरण का दबाव बढ़ा। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियमों के तहत सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यों में निष्पक्षता और ईमानदारी बनाए रखना अनिवार्य है। इन नियमों में कर्मचारियों को राजनीतिक दलों की सक्रिय सदस्यता लेने और राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होने से स्पष्ट रूप से रोका गया है। सरकार का कहना है कि वापस लिया गया सर्कुलर इन्हीं प्रावधानों की पुनरावृत्ति मात्र था, लेकिन विपक्ष ने इसे राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित कदम बताया। आदेश वापस लेकर साय सरकार ने फिलहाल विवाद को शांत करने की कोशिश की है।

बंगाल में 'मां-माटी-मानुष' का अपमान हुआ, जनता वोट से देगी जवाब - नितिन नवीन

नैहाटी, (एजेंसी)। पश्चिम बंगाल की 152 विधानसभा सीटों पर गुरुवार को पहले चरण के तहत वोटिंग होगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने दावा किया कि गुरुवार से ममता की आराजकता वाली सरकार का समापन शुरू होगा। नैहाटी में नितिन नवीन ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता अपनी पहली मुक्ति के लिए वोट करेगी। वे टीएमसी सरकार को हटाने के लिए वोट करेंगे। जिस प्रकार से टीएमसी के गुंडों ने हफ्ता वसूली और रंगदारी की और लोगों को प्रताड़ित किया है, जिस रमां, माटी, मानुष के नारे के साथ टीएमसी सरकार सत्ता में आई थी, उन्होंने उसका भी अपमान किया है। इसलिए अब इस सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। पश्चिम बंगाल की जनता इसकी शुरुआत गुरुवार को होने वाले पहले चरण की वोटिंग से करेगी। उन्होंने कहा कि टीएमसी के लोग आराजकतावादी हैं। ये संविधान और संविधान में निर्धारित प्रक्रियाओं में विश्वास नहीं रखते। ये अपनी सत्ता और अपने शासन में विश्वास रखते हैं। ये संविधान के कानूनों को नहीं मानते। और यही कारण है कि इन्हें हर तरफ से फटकार पड़ रही है। पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर निंदा करते हुए नितिन नवीन ने कहा कि मेरा मानना है कि जब भी कांग्रेस ने इतनी गिरी हुई बातें की हैं तो जनता ने उसे जवाब दिया है, और इस बार भी देगी। नितिन नवीन ने कहा कि जब-जब कांग्रेस ने मोदी का अपमान किया, तब-तब देश की जनता मोदी को जीत का हार पहनाती है। राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है।



राजस्थान को वैश्विक शिक्षा केंद्र के रूप में उभरना चाहिए - ओम बिरला

जयपुर, (एजेंसी)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने बुधवार को कहा कि राजस्थान में वैश्विक स्तर पर शिक्षा का अग्रणी केंद्र बनने की क्षमता है, जो दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित कर सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह सपना सामूहिक प्रयासों, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के माध्यम से साकार किया जा सकता है। बिरला ने राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के साथ बुधवार को जयश्री पेरौला ग्लोबल स्कूल के नए परिसर का उद्घाटन किया। दोनों गणमान्य व्यक्तियों ने आधुनिक परिसर का दौरा किया और अत्याधुनिक कक्षाओं और सुविधा



ओं का जायजा लिया। सभा को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि भारत का संविधान विस्मय के लोकतंत्रों के लिए मार्गदर्शक है और लोकतंत्र को राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति बताया। उन्होंने

नागरिकों से तेजी से बदलते भारत के भविष्य को आकार देने में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। वासुदेव देवनानी ने इस अवसर को महज एक भवन के उद्घाटन से कहीं अधिक बताया

और इसे भारत के उज्वल भविष्य के द्वार की शुरुआत बताया। शिक्षा के व्यापक अर्थ पर जोर देते हुए देवनानी ने कहा कि यह केवल साक्षरता तक सीमित नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली शक्ति है जो मानवीय क्षमता को जागृत करती है और व्यक्तियों को साधारण से असाधारण बनाती है। भारत की समृद्ध शैक्षणिक विरासत का जिक्र करते हुए राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष ने नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन शिक्षा केंद्रों का उल्लेख किया और कहा कि भारत ऐतिहासिक रूप से ज्ञान का वैश्विक केंद्र रहा है। उन्होंने कहा कि सदियों से चुनौतियों के बावजूद, देश की ज्ञान परंपरा अटूट बनी हुई है।

भाजपा तमिलनाडु की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को खत्म कर देगी - राहुल गांधी

नई दिल्ली, (एजेंसी)। तमिलनाडु विधानसभा के सभी 234 सदस्यों के चुनाव के लिए 23 अप्रैल को मतदान होना है। इस बीच कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राज्य के लोगों से कांग्रेस-डीएमके गठबंधन को समर्थन देने की अपील की है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी एक वीडियो संदेश में कहा कि तमिलनाडु में यह चुनाव कांग्रेस पार्टी-डीएमके गठबंधन और भाजपा-एआईएडीएमके गठबंधन के बीच विचारधारा की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि भाजपा एआईएडीएमके को कंट्रोल करती है और तमिलनाडु में किसी भी तरह प्रवेश करने की कोशिश में जुटी है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो वो तमिलनाडु की संस्कृति, भाषा और परंपराओं को खत्म कर देंगे। एआईएडीएमके नेतृत्व अपने भ्रष्टाचार के कारण भाजपा के दबाव में है। वहीं, प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में हैं और एआईएडीएमके नेतृत्व प्रधानमंत्री के दबाव में है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा दिल्ली से तमिलनाडु को चलाना चाहती है। भाजपा तमिलनाडु में कठपुतली मुख्यमंत्री और दूरस्थ नियंत्रण वाली सरकार चाहती है। इंडिया गठबंधन ऐसा कभी नहीं होने देगा। तमिलनाडु अपनी पहचान और गरिमा की रक्षा के लिए मतदान करेगा। लेकिन, हम चाहते हैं कि तमिलनाडु के लोग ही तमिलनाडु पर शासन करें। हम चाहते हैं कि तमिलनाडु में वहीं का मुख्यमंत्री हो, जो वहां के लिए और वहां के लोगों के लिए काम करे। उन्होंने कहा कि हम तमिलनाडु में सामाजिक न्याय के पक्ष में हैं।



अब एक पास पर आठ की जगह सिर्फ पांच श्रद्धालु ही कर सकेंगे रामलला का कर सकेंगे दर्शन

(डॉ) अजय तिवारी
जिला संवाददाता)
अयोध्या। राम मंदिर पर बढ़ते श्रद्धालुओं तथा भारी भीड़ को देखते हुए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े इसके लिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बीच बीच में कोई ना कोई कदम उठाता रहता है। इसी कड़ी में शुकवार को श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर परिसर में दर्शन व्यवस्था को और सुव्यवस्थित बनाने के लिए अहम बदलाव किए हैं। जिसमें ट्रस्ट द्वारा यह बड़ा बदलाव किया गया है कि अब एक पास पर अधिकतम 5 श्रद्धालु ही दर्शन कर सकेंगे। जबकि इसके पहले एक पास

पर आठ श्रद्धालु राम मंदिर में जाकर दर्शन पूजन कर सकते थे। ट्रस्ट का कहना है कि इससे भीड़ प्रबंधन बेहतर होगा और सभी को समान अवसर मिल सकेगा। हालांकि, बढ़ती भीड़ के कारण 8 मई तक सुगम और सामान्य दोनों ही दर्शन के सभी स्लॉट पहले से ही फुल हो चुके हैं। विशिष्ट दर्शन पास ट्रस्ट और प्रशासनिक अधिकारियों के कोटे से जारी होते हैं और यह सुविधा वेबसाइट पर उपलब्ध नहीं है। ट्रस्ट ने श्रद्धालुओं को भारतीय पारंपरिक परिधान में दर्शन करने की सलाह भी दी है। वेबसाइट के अनुसार पुरुष ६ फीट-कुर्ता या कुर्ता-पायजामा, जबकि महिलाएं साड़ी या सलवार-कुर्ता पहनकर दर्शन कर

सकती हैं। हालांकि, इसे अनिवार्य नहीं किया गया है। परकोटा के छह नए मंदिरों और सप्तर्षि मंदिर के निर्माण व ध्वजारोहण के बाद अब दर्शन प्रणाली को नया स्वरूप दिया गया है। वहीं ट्रस्ट ने लोगों से भारतीय परिधान में दर्शन करने की अपील की है। अब श्रद्धालुओं के लिए दो प्रकार के पास जारी किए जा रहे हैं। इस समय सुगम दर्शन और सामान्य दर्शन होगा। सुगम दर्शन पास के जरिए श्रद्धालु रामलला, राम परिवार और परकोटा के छह मंदिरों के दर्शन कर सकेंगे। वहीं सामान्य दर्शन पास में रामलला, राम परिवार, शेषावतार मंदिर, सप्तर्षि मंदिर और कुबेर टीले के दर्शन शामिल किए गए हैं।



संपादकीय

ईरान के इरादे अलग

संभवतरू पाकिस्तान ने इस सोच के साथ मध्यस्थ बनना स्वीकार किया था कि अमेरिका की शर्तें ही वार्ता का आधार बनेंगी, जिन पर ले–देकर सहमति बन जाएगी। लेकिन ईरान के इरादे अलग हैं। वह आर–पार की लड़ाई के मूड में है। पश्चिम एशिया में युद्ध खत्म कराने के लिए पाकिस्तान की मध्यस्थता किसी नतीजे पर पहुंचती नहीं दिखती। अमेरिका की शर्तें उसने ईरान को बताईं, मगर ईरान ने उसे टुकराते हुए अपनी जवाबी मांग पाकिस्तान को बता दी। पाकिस्तान उस पर अमेरिका से बातचीत करने की हैसियत में है या नहीं, यह नहीं मालूम। मगर इस बीच उसने अपने यहां तीन अन्य देशों (सऊदी अरब, मिस्र और तुर्किये) के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की। समझा जाता है कि उसके नतीजों को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार बीजिंग गए। लेकिन वहां जारी साझा बयान से नहीं लगता कि चीन ने उसमें दिलचस्पी दिखाई है। साझा बयान में सामान्य भाषा का इस्तेमाल किया गया है। समझा जाता है कि पाकिस्तान ने चीन से आगे ईरान पर हमला ना होने की गारंटी करने की जिम्मेदारी लेने का अनुरोध किया। मगर फिलहाल चीन ने इस टुकरा दिया है। दरअसल, पश्चिम एशिया में अमेरिकी अड़े स्थायी रूप से हटाने, नुकसान का मुआवजा देने, और होरमुज जलडमरूमध्य पर ईरानी संप्रभुता को मान्यता देने की ईरान की मांगों पर कोई रजामंदी जब तक नहीं होती, आगे हमला ना होने की गारंटी कोई नहीं कर सकता। इन मांगों पर बातचीत से सहमति बनेगी, इसकी संभावना न्यूनतम है। अतरू लड़ाई तुरंत खत्म होने की कोई सुरत नहीं है। बेशक, अमेरिका में बढ़ती चुनौतियों के मद्देनजर डॉनल्ड ट्रंप युद्ध से निकलने का रास्ता ढूढ़ रहे हैं, मगर लड़ाई में इजराइल भी शामिल है। ईरान की जीत की धारणा को पुष्ट करते हुए वह युद्ध खत्म करने को शापव् ही तैयार होगा। दरअसल, ऐसा हुआ तो इजराइल का अस्तित्त्व खतरे में पड़ता दिखेगा, जिसे अमी चार तरफ से (ईरान, हिज्बुल्लाह, हूती और इराक स्थित पीएमएफ) हमलों को झेलना पड़ रहा है। इसलिए, मध्यस्थता प्रयासों के फिलहाल सफल होने की संभावना कम है। चीन की कूटनीतिक प्रतिक्रिया इसी आकलन का संकेत देती है। संभवतरू पाकिस्तान ने इस सोच के साथ मध्यस्थ बनना स्वीकार किया कि अमेरिका की शर्तें ही वार्ता का आधार बनेंगी, जिन पर ले–देकर सहमति बन जाएगी। लेकिन ईरान के इरादे अलग हैं। वह आर–पार की लड़ाई के मूड में है।

मतदान की प्रक्रिया में गड़बड़ी होती रही

अजीत द्विवेदी
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रविवार, 22 मार्च को इंडियन एक्सप्रेसच में अपने साप्ताहिक कॉलम में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर में कटने वाले नामों के आंकड़े दिए, उस पर आ्धारित एक निष्कर्ष निकाला और एक दिलचस्प सवाल उठाया। उन्होंने लिखा कि लाखों वयस्क लोग, औसतन 10 फीसदी, मतदाता सूची से गायब हैं। इसके बाद उन्होंने सवाल उठाया, शक्या गायब लोग वयस्क हैं, हां। क्या वे लोग नागरिक हैं, हां, जब तक कि इसके उलट कोई बात प्रमाणित नहीं होती है, फिर वे क्यों गायब हैंच? बहुत दिलचस्प है यह सवाल। वे कह रहे हैं कि हर राज्य की वयस्क आबादी में से औसतन 10 फीसदी लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं शामिल किए जा रहे हैं और चूंकि उनको विदेशी या घुसपैटिया भी नहीं बताया जा रहा है फिर उनके नाम क्यों काटे जा रहे हैं? उनको लेख के साथ आंकड़ों की टेबल है, जिसमें बताया गया है कि एसआईआर से पहले की मतदाता सूची के मुकाबले एसआईआर के बाद की मतदाता सूची में बिहार में छह फीसदी, छत्तीसगढ़ में 12 फीसदी, केरल में साढ़े तीन फीसदी, मध्य प्रदेश में छह फीसदी, राजस्थान में छह फीसदी, तमिलनाडु में साढ़े 12 फीसदी नाम कटे हैं। उन्होंने बताया है कि बिहार में पहले कुल वयस्क आबादी में से 96.7 फीसदी लोगों के नाम मतदाता सूची में थे, जबकि एसआईआर के बाद आई सूची में 90.7 फीसदी लोगों के नाम हैं। यानी वयस्क आबादी में से 9.3 फीसदी लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं। उन्होंने सात राज्यों के आंकड़े दिए हैं। सबसे दिलचस्प आंकड़ा उनके अपने राज्य तमिलनाडु का है। एसआईआर से पहले तमिलनाडु की वयस्क आबादी के मुकाबले 106.8 फीसदी नाम मतदाता सूची में थे और अब 94.3 फीसदी हैं। उम्मीद थी कि टेबल में दिए गए इस आंकड़े की वे कुछ व्याख्या करेंगे और बताएंगे कि अनुमानित वयस्क आबादी से करीब सात फीसदी ज्यादा मतदाता तमिलनाडु की मतदाता सूची में कैसे थे और इनके नाम कट गए तो ये लोग कलम करने के लिए आगे क्यों नहीं आए? लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। पी चिदंबरम ने अपने लेख में यह बताने की कोशिश की है और बड़े मासूम तरीके से की है कि हर राज्य में जितने वयस्क नागरिक हैं लगभग उतने नाम मतदाता सूची में होने चाहिए। सवाल है कि क्या वे इतने नासमझ हैं कि मौजूदा समय के बदलावों को नहीं समझ रहे हैं? क्या देश के अंदर और बाहर हुए पलायन या प्रवासन की परिघटना को चिदंबरम नहीं समझते हैं? क्या वे जनगणना में होने वाली गड़बड़ियों और गिनती में दोहराव की संभावना को नहीं समझते हैं? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की ओर से एक रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसके मुताबिक 2023 में भारत में प्रवासन की दर 28.88 फीसदी थी। यह 2011 के मुकाबले लगभग 12 फीसदी कम थी। फिर भी संख्या के लिहाज से देखें तो देश के 40 करोड़ से ज्यादा लोग अपने मूल निवास से दूर किसी दूसरे जिले या किसी दूसरे राज्य में रहते थे। बिबेक देबरॉय और देवी प्रसाद मिश्र द्वारा तैयार की गई इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 75 फीसदी के करीब लोग पांच सौ किलोमीटर के दायरे में गए थे। इसे गुरुत्वाकर्षण प्रभाव कहा गया है। करीब 25 फीसदी लोग पांच सौ किलोमीटर के दायरे से बाहर थे। यानी लगभग 10 करोड़ लोग ऐसे थे, जो अपने मूल निवास से पांच सौ किलोमीटर दूर जाकर रहते थे। वे काम के सिलसिले में गए या कारोबार के सिलसिले में या शिक्षा के लिए गए यह अलग बात है। 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरेलू प्रवासन के अलावा लगभग साढ़े तीन करोड़ भारतीयों ने अंतरराष्ट्रीय प्रवासन किया है। यानी विदेश में रहते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल करीब 25 लाख लोग भारत से विदेश जा रहे हैं। अगर 2011 की जनगणना के आंकड़ों को देखें तो उत्तर प्रदेश के करीब एक करोड़ 10 लाख लोग देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं, जबकि बिहार के 60 लाख लोग अलग अलग राज्यों में रहते हैं। इनमे से सबसे ज्यादा करीब 14 लाख लोग झारखंड में रहते हैं। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में कट रहे नामों के आधार पर पी चिदंबरम ने एक एकपक्षीय निष्कर्ष निकाला है। उन्होंने इसके दूसरे पहलुओं की व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं समझी है। जैसे घरेलू और विदेशी प्रवासन के आंकड़े को उन्होंने संज्ञा में नहीं लिया।

विचार

ब्रिगेड मैदान की जंग में ममता बनाम अभित शाह की जंग



उमेश प्रधानमंत्री रहते अटल बिहारी वाजपेयी ने कोलकाता की यात्रा की थी। उस दौर पर उन्होंने तत्कालीन रेल मंत्री के कालीघाट स्थित घर का दौरा किया था। तब उन्होंने मंत्री की मां से उलाहना दिया था, आपकी बेटी मुझे बहुत परेशान करती हैं। कहना न होगा कि वह शक्ति्सयत डेढ़ दशक से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। ममता बनर्जी लड़का है। धूल से उठकर राजनीतिक असमान का तारा अगर वे बनी हुई हैं, उसकी वजह उनका सघर्षशील व्यक्तित्व ही है। लेकिन कोलकाता के मैदान में इस बार यह योद्धा फंसा नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह उनसे दो–दो हाथ कर रही है, निश्चित तौर पर उसके पीछे नरेंद्र मोदी की अगुआई में बंगाल की धूल में लगातार परिश्रम कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। आज अगर बंगाली की सियासी लड़ाई आर–पार के दौर में आ चुकी है तो

ममता बनर्जी, अमित शाह

अमित शाह, ममता बनर्जी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

इसके पीछे अमित शाह की रणनीति काम कर रही है। साल 2021 के विधानसभा चुनाव नतीजे आने के बाद कहा गया था कि बीजेपी चुनाव जीतते–जीतते हार गई है। ममता का संघर्ष बीजेपी की रणनीतियों पर भारी पड़ गया था। पांच साल बाद कोलकाता के रायटर्स बिल्डिंग पर कब्जे को लेकर सेनाएं सज गई हैं। लेकिन इस बार हालात बदले नजर आ रहे हैं। बनर्जी लड़का है। धूल से उठकर प्रचार की कमान खुद संभालना की जिन्होंने 170 सीटें जीतने का महत्वाकंक्षी लक्ष्य तय कर रखा है। पिछले विधानसभा चुनाव में पिछड़ने के बावजूद अमित शाह ने राज्य की यात्राएं जारी रखीं और इसके जरिए अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित बनाए रखा। इस बार बीजेपी अगर सत्ता की प्रबल दावेदार के रूप में उभरी है तो इसकी बड़ी वजह बूथ प्रबंधन तो है ही, घुसपैट और महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाना भी है। बंगाल के बारे में कहा जाता है कि

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

अमित शाह, ममता बनर्जी

वह जो आज सोचता है, पूरा देश उस पर बाद में आगे बढ़ता है। शक्ति पूजा की संस्कृति वाले राज्य में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ममता के राज में कई बार सवाल उठे। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कालेज में रेजिडेंट डाक्टर से दुष्कर्म और बर्बर हत्या के बाद अंग्रेजों की पहली राजधानी का भद्रलोक उद्देलित हो उठा। अभी इसकी आंच ठंडी पड़ी नहीं कि कस्बा लॉ कालेज की छात्रा के साथ बलात्कार हुई। इसके पहले संदेशखाली में हुई कथित तौर पर यौन हिंसा और जमीन हड़पने के मामलों से पश्चिम बंगाल का समाज उद्देलित रहा। अमित शाह इसकी वजह अमित शाह का चुनाव प्रचार की कमान खुद संभालना की जिन्होंने 170 सीटें जीतने का महत्वाकंक्षी लक्ष्य तय कर रखा है। पिछले विधानसभा चुनाव में पिछड़ने के बावजूद अमित शाह ने राज्य की यात्राएं जारी रखीं और इसके जरिए अपने कार्यकर्ताओं को उत्साहित बनाए रखा। इस बार बीजेपी अगर सत्ता की प्रबल दावेदार के रूप में उभरी है तो इसकी बड़ी वजह बूथ प्रबंधन तो है ही, घुसपैट और महिला सुरक्षा को मुद्दा बनाना भी है। बंगाल के बारे में कहा जाता है कि

अस्थिर विश्व में भारत–अर्थनीति, कूटनीति

विश्वास और प्रभाव अर्जित नहीं कर सका
पिछले एक दशक में जब–जब विश्व में संघर्ष और अशांति बढ़ी, प्रधानमंत्री द्वारा श्यह युद्ध का युग नहीं है, की बात तो बार–बार कही गई, किंतु उसके अनुरूप कोई ठोस शांति–योजना सामने नहीं आई। संयुक्त राष्ट्र में युद्धविराम प्रस्तावों पर मतदान से दूरी बनाकर भारत ने तटस्थता का संकेत देने का प्रयास किया, परंतु अंतरराष्ट्रीय समुदाय के एक हिस्से ने इसे निष्पक्षता के बजाय अनिर्णय के रूप में देखा। परिणामस्वरूप, जहां नेहरू युग में भारत कोरियाई और वियतनामी संकटों में मध्यस्थता के लिए जाना जाता था, वहीं आज उसकी वह भूमिका अपेक्षाकृत सीमित हो गई है।टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में रणबीर गूपल (अभिनेता), सुंदर पिचाई (सीईओ गूगल) और विकास खन्ना (पाककला) पर उठते प्रश्नों ने सांख्यिकीय साख पर भी अनावश्यक प्रश्नचिह्न खड़े किए। इस सूची में स्थान पा चुके प्रधानमंत्री मोदी का इस बार अनुपस्थित रहना विशेष रूप से तब ध्यान आकर्षित करता है, जब नेपाल और बांग्लादेश के अपेक्षाकृत नए नेतृत्व को इसमें स्थान मिला है। यह स्थिति भारत की

गुटबाजी को भी सुलझाने की कोशिश की। राज्य में पार्टी के अध्यक्ष रहे दिलीप घोष के बारे में माना जा रहा था कि वे नाखुश हैं। अमित शाह ने उनसे मुलाकात करके तृणमूल से आए शुभेंदु अधिकारी से बीच उनके मतभेदों को दूर करने की कोशिश की। ममता बनर्जी ने पिछली बार बंगाली माटी और मानुष यानी स्थानीय को मुद्दा बनाया था। उन्हें इस मुद्दे से पिछली बार मदद भी मिली। इस बार भी ममता विपक्ष यानी बीजेपी के नेताओं के बाहरी होने का आरोप लगा रही हैं। इसके जवाब स्वरूप अमित शाह ने ऐलान किया है कि अगर पश्चिम बंगाल में पार्टी सत्ता में आई तो राज्य का मुख्यमंत्री ‘धरती का बेटा’ यानी स्थानीय व्यक्ति ही बनेगा। पार्टी ने इस बार घुसपैठ को भी बड़ा मुद्दा बनाया है। राज्य में विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान राज्य में नब्बे लाख वोटरों के नाम हटाने के लेकर ना सिर्फ सत्तारूि तृणमूल कांग्रेस समेत समूचा गैर बीजेपी दल मुद्दा बना रहे हैं। हालांकि अमित शाह चुनाव आयोग के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर के कदम को सही बताया है। बीजेपी यहीं नहीं रूकी है, उसने वादा किया है कि अगर वह सत्ता में आई तो राज्य से अवैध घुसपैठियों की पहचान करेगी और उन्हें बाहर करेगी। इसके साथ ही पार्टी ने सत्ता में आने के पैंतालीस दिनों के अंदर सीमा पर बाड़ लगाने के लिए केंद्र सरकार को

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी



घरेलू वृद्धि सुदृढ़ बनी रही। यह स्थिति अल्पकालिक दबाव को कुछ हद तक नियंत्रित किया, किंतु यह हस्तक्षेप रुपये की निरंतर गिरावट को रोक कर उसे अपेक्षित स्थिरता प्रदान करने में पूर्णतः सफल नहीं हो सका। परिणामस्वरूप, डॉलर की मजबूती और भू–राजनीतिक तनावों से रुपये पर बने दबाव पर निर्णायक नहीं बन सका। इटली सहित यूरोप के कई देशों में सरकार और जनता के स्तर पर इजरायल के प्रति रूख में आया बदलाव यह संकेत

अमित शाह, ममता बनर्जी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

अमित शाह, ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी

